

मजदूरी संहिता, 2019

- प्रश्न 1 मजदूरी संहिता, 2019 के तहत कितने मौजूदा अधिनियमों को शामिल किया गया है और वे कौन से हैं?
- उत्तर. मजदूरी संहिता, 2019 के तहत मौजूदा चार अधिनियमों को शामिल किया गया है और वे इस प्रकार हैं: मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।
- प्रश्न 2 मजदूरी संहिता, 2019 के तहत शुरू किए गए मूलभूत सुधार क्या हैं?
- उत्तर. मजदूरी संहिता, 2019 के तहत शुरू किए गए मूलभूत सुधारों में शामिल हैं: i) न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी के समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाया गया है; ii) परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को न्यूनतम कर दिया गया है, तथा iii) निरीक्षक की भूमिका को निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता में बदल दिया गया है।
- प्रश्न 3. क्या मजदूरी संहिता, 2019 'अनुसूचित रोजगार' की अवधारणा को बरकरार रखती है?
- उत्तर. नहीं।
- प्रश्न 4. क्या किसी प्रतिष्ठान में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति मजदूरी संहिता, 2019 के तहत परिभाषित 'कर्मचारी' की परिभाषा में आते हैं?
- उत्तर. हाँ।
- प्रश्न 5. मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना है, के संबंध में नियोक्ता कौन है?
- उत्तर. कारखाने का कब्जेदार और जहां किसी व्यक्ति को फैक्ट्री के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार नामित व्यक्ति मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठान का नियोक्ता होगा।
- प्रश्न 6. क्या मजदूरी संहिता, 2019 किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कर्मचारियों के बीच समान या समान प्रकृति के काम के संबंध में समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव की अनुमति देती है।
- उत्तर. नहीं।
- प्रश्न 7. मजदूरी संहिता, 2019 के संदर्भ में 'समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य' से क्या तात्पर्य है?
- उत्तर. 'समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य' का अर्थ वह कार्य है जिसके संबंध में आवश्यक कौशल, श्रम, अनुभव और उत्तरदायित्व समान होते हैं और कर्मचारियों द्वारा समान कार्य परिस्थितियों में किया जाता है और मतभेद, यदि कोई हो, रोजगार के नियमों और शर्तों के संबंध में व्यावहारिक महत्व नहीं रखते हैं।

प्रश्न 8. मजदूरी संहिता, 2019 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण या संशोधन के लिए दो तरीके क्या हैं?

उत्तर. i) जांच करने और सिफारिशें करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा जितनी उपयुक्त समझी जाए उतनी समितियों की नियुक्ति;

ii) ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके प्रस्तावों की अधिसूचना का प्रकाशन।

प्रश्न 9. मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार वेतन की परिभाषा में कौन से घटक शामिल हैं?

उत्तर. मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार वेतन की परिभाषा में शामिल घटक हैं: मूल वेतन; महंगाई भत्ता; और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो।

प्रश्न 10. क्या मजदूरी संहिता, 2019 केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारण का प्रावधान करती है और यह किस उद्देश्य को पूरा करता है?

उत्तर. हाँ, मजदूरी संहिता, 2019 इसका प्रावधान करती है। संहिता की धारा 9(1) के अनुसार इसकी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, जिसे निर्धारित तरीके से किसी कर्मचारी के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखना होगा और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी तय की जा सकती है। संहिता की धारा 9(2) में प्रावधान है कि संहिता की धारा 6 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी।

प्रश्न 11. किसी कर्मचारी द्वारा किए गए ओवरटाइम काम के लिए मजदूरी के भुगतान की दर क्या है, जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी संहिता, 2019 के तहत घंटे द्वारा, दिन द्वारा या किसी ऐसी मजदूरी अवधि के आधार पर, जो विहित की जाए, के अनुसार तय की गई है।

उत्तर. मजदूरी की सामान्य दर के दोगुने से कम नहीं (मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 14)।

प्रश्न 12. समय कार्य के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में, मजदूरी संहिता, 2019 के तहत अलग-अलग वेतन अवधि क्या हैं?

उत्तर. समय कार्य के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में चार संभावित मजदूरी अवधि हैं यानी i) दैनिक, (ii) साप्ताहिक, (iii) पाक्षिक और (iv) मासिक, इस शर्त के अधीन कि किसी कर्मचारी के संबंध में कोई भी मजदूरी अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

प्रश्न 13. मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार समय कार्य के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में सामान्य परिस्थितियों में मजदूरी भुगतान की समय सीमा क्या है?

उत्तर. समय सीमा इस प्रकार है:

दैनिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान शिफ्ट के अंत में किया जाना है।

साप्ताहिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस यानी साप्ताहिक अवकाश से पहले करना होगा।

पाक्षिक आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भुगतान पखवाड़े की समाप्ति के बाद दूसरे दिन की समाप्ति से पहले करना होगा।

मासिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान अगले महीने के सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जहां किसी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या छंटनी कर दी गई है या कर्मचारी ने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, या प्रतिष्ठान बंद होने के कारण कर्मचारी बेरोजगार हो गया है, तो उसे देय मजदूरी का भुगतान उसके निष्कासन, बर्खास्तगी, छंटनी, या जैसा भी मामला हो, उसके इस्तीफे के दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

प्रश्न 14. प्राधिकरी द्वारा दावे का निर्धारण करने के लिए मजदूरी संहिता के तहत निर्धारित समय सीमा क्या है?

उत्तर. तीन माह।

प्रश्न 15. संहिता के तहत अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान के मामले में प्राधिकरी द्वारा निर्धारित दावे के अलावा मजदूरी संहिता, 2019 के तहत दावा प्राधिकरी द्वारा कितना मुआवजा दिया जा सकता है?

उत्तर. निर्धारित दावे का 10 गुना तक।

प्रश्न 16. मजदूरी संहिता के अनुसार, पहली बार देय मजदूरी से कम भुगतान करने पर नियोक्ता पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

उत्तर. ₹ 50,000/- तक ।

प्रश्न 17. मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार, केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों में स्वतंत्र सदस्यों का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना होगा?

उत्तर. कुल सदस्यों का एक तिहाई।

प्रश्न 18. देय मजदूरी से कम भुगतान करने के अपराध में दोषी पाए जाने पर और पहले या उत्तरवर्ती अपराध की तारीख से 5 साल के भीतर दोबारा उसी अपराध में दोषी पाए जाने पर नियोक्ता पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ?

उत्तर. 3 महीने तक की कैद या ₹ एक लाख तक का जुर्माना या दोनों।

प्रश्न 19. मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार नियोक्ता द्वारा किए गए किस प्रकार के अपराध को राजपत्रित अधिकारी द्वारा उपशमन (कंपाउंड) किया जा सकता है?

उत्तर. केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध को।

प्रश्न 20. वह राशि क्या है जिसके लिए नियोक्ता द्वारा किए गए अपराध को मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा उपशमन (कंपाउंड) किया जा सकता है?

उत्तर. ऐसे अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने की 50% राशि का प्रावधान है।
